8 पर्यावरणीय प्रभाव आकलन
(Environmental Impact Assessment)

भूमिका *(Introduction)*

पर्यावरणीय प्रभाव आकलन (Environmental Impact Assessment – EIA) किसी प्रस्तावित परियोजना अथवा क्रियाकलाप के पर्यावरण पर पड़ने वाले संभावित प्रभावों के अध्ययन के रूप में जाना जाता है। पर्यावरणीय प्रभाव आकलन किसी परियोजना के लिये संभावित विविध विकल्पों की तुलना करता है एवं ऐसे विकल्प चुनने में मदद करता है जो परियोजना के पर्यावरणीय एवं आर्थिक मूल्य के दृष्टिकोण से सर्वश्रेष्ठ हो।

पर्यावरणीय प्रभाव आकलन व्यवस्थित ढंग से परियोजना के लाभकारी एवं हानिकारक दोनों प्रकार के प्रभावों का आकलन करता है। यह प्रस्तावित परियोजना के संभावित पर्यावरणीय प्रभावों की पहचान करने में मदद करता है, प्रतिकूल प्रभावों की गंभीरता कम करने अर्थात् शमन (Mitigation) करने के लिये सुझाव प्रस्तुत करता है तथा उन महत्त्वपूर्ण पर्यावरणीय प्रभावों का अनुमान लगाता है जो शमन के बावजूद उत्पन्न हो सकते हैं। परियोजना के प्रारंभ में ही इसके पर्यावरणीय प्रभावों एवं उनके शमन को ध्यान में रखते हुए योजना बनाने से पर्यावरणीय प्रभाव आकलन के काफी लाभकारी प्रभाव हो सकते हैं, जैसे- पर्यावरण संरक्षण, संसाधनों का इष्टतम उपयोग और परियोजना के समय तथा लागत की बचत आदि। उचित ढंग से किया हुआ पर्यावरणीय प्रभाव आकलन सामुदायिक सहभागिता बढ़ाकर विवादों को कम करता है, नीति-निर्माताओं तक सूचनाएँ सुलभ कराता है एवं पर्यावरणीय परियोजनाएँ स्थापित करने में मदद करता है। एकीकृत पर्यावरणीय प्रभाव आकलन के लाभों को परियोजना के प्रत्येक चरण में महसूस किया जा सकता है।

पर्यावरणीय प्रभाव आकलन का विकास क्रम *(Development Sequence of Environmental Impact Assessment)*

'पर्यावरणीय प्रभाव आकलन' की संकल्पना एवं विधि का उद्भव 1969 में संयुक्त राज्य अमेरिका में नेशनल एनवायरनमेंटल पॉलिसी एक्ट (NEPA) के पारित होने के साथ हुआ। 1 जनवरी, 1970 को राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन ने इस पर हस्ताक्षर किया। इस अधिनियम के उद्देश्य-

- मनुष्य एवं पर्यावरण के मध्य मधुर संबंध स्थापित करने के लिये राष्ट्रीय नीति की घोषणा करना।
- पर्यावरण एवं जीवमंडल की क्षति को रोकने या पूर्णतया समाप्त करने के लिये प्रयास करना तथा मनुष्य के स्वास्थ्य एवं कल्याण के लिये कार्य करना।
- राष्ट्र के लिये उपयोगी प्राकृतिक संसाधनों तथा पारिस्थितिकी तंत्रों की समझ को बढ़ाना।
- पर्यावरणीय गुणवत्ता परिषद् (Council on Environmental Quality : CEQ) की स्थापना करना।

संयुक्त राज्य अमेरिका में 'राष्ट्रीय पर्यावरण नीति अधिनियम' (NEPA) के लागू होते ही भविष्य में क्रियान्वित होने वाली सभी कार्य-योजनाओं के लिये पर्यावरणीय प्रभाव आकलन को अनिवार्य

पर्यावरण प्रबंधन योजना *(Environment Management Plan)*

पर्यावरण के प्रत्येक घटक के लिये नियंत्रण, पुनर्वास एवं पुनर्स्थापना; शर्तों के अनुपालन के लिये योजना; समय निर्धारण और संसाधनों के आवंटन आदि योजना के लिये प्रारूप तैयार किये जाते हैं।

रणनीतिक पर्यावरण आकलन *(Strategic Environmental Assessment : SEA)*

विकास की नीतियों, योजनाओं, कार्यक्रमों और अन्य प्रस्तावित रणनीतिक कार्यों के पर्यावरणीय प्रभाव के व्यवस्थित विश्लेषण को रणनीतिक पर्यावरण आकलन कहा जाता है। SEA उच्च स्तरीय निर्णयन प्रक्रिया में पर्यावरणीय दृष्टिकोण को एकीकृत करने के लिये सक्रिय भूमिका निभाता है। पर्यावरणीय प्रभाव आकलन के व्यापक उपयोग एवं स्वीकृति के बावजूद इसके विकास परियोजनाओं के पर्यावरणीय प्रभाव को कम करने के उपकरण के रूप में कुछ कमियाँ हैं। इसी कारण रणनीतिक पर्यावरणीय आकलन का सिद्धांत चर्चा में आया।

पर्यावरणीय प्रभाव आकलन (EIA)	रणनीतिक पर्यावरण आकलन (SEA)
• यह निर्णय लेने की प्रक्रिया के अंत में जगह लेता है।	• यह निर्णय लेने की प्रक्रिया के पहले चरण से ही स्थान लेता है।
• विकास प्रस्तावों के लिये प्रतिक्रियाशील (Reactive) दृष्टिकोण।	• विकास प्रस्तावों के लिये सक्रिय (Proactive) दृष्टिकोण।
• संभावित विकल्पों की सीमित संख्या पर विचार।	• संभावित विकल्पों की व्यापक सीमा पर विचार।
• संचयी प्रभाव की सीमित समीक्षा।	• संचयी प्रभाव की पूर्व चेतावनी।
• न्यूनीकरण (Mitigation) पर ज़ोर।	• पर्यावरण उद्देश्यों को पूरा करने एवं प्राकृतिक प्रणालियों को बनाए रखने पर ज़ोर।
• अच्छी तरह से परिभाषित प्रक्रिया, स्पष्ट शुरुआत व अंत।	• कई चरणों की प्रक्रिया जिसके घटकों में अतिव्याप्तता (ओवरलैपिंग)।
• मानक एजेंडे पर केंद्रित पर्यावरण अवनयन के लक्षणों का प्रबंधन करता है।	• स्थिरता के एजेंडे पर केंद्रित है, पर्यावरण अवनति के स्रोतों पर ही किया जाता है।

EIA व SEA में अंतर

1990 तक SEA का विकास एवं कार्यान्वयन सीमित मात्रा में हुआ था। 1990 के पश्चात् अनेक विकसित देशों ने SEA को अपनाया। कनाडा एवं डेनमार्क जैसे कुछ देशों ने EIA की योजनाओं एवं नीतियों से अलग SEA के प्रावधान बनाए थे। अन्य देशों, जैसे- चेक गणराज्य, स्लोवाकिया आदि ने EIA कानून में संशोधन कर SEA आवश्यकताओं को प्रस्तुत किया। यूनाइटेड किंगडम ने पर्यावरणीय मूल्यांकन के माध्यम से SEA को लागू किया था। ऑस्ट्रेलिया एवं न्यूज़ीलैंड में यह संसाधन प्रबंधन एवं जैव विविधता संरक्षण व्यवस्थाओं का भाग है। यूरोपीय यूनियन के दिशानिर्देशों एवं UNECE (United Nation Economic Commission for Europe) कन्वेंशन के हस्ताक्षरकर्ता देशों में आने वाले वर्षों में SEA का प्रयोग तीव्र गति से बढ़ सकता है।

भारत में पर्यावरणीय प्रभाव आकलन की कमियाँ *(Shortcomings of EIA in India)*

भारत में किये जाने वाले पर्यावरणीय प्रभाव आकलन में अनेक कमियाँ दिखाई देती हैं। ये निम्नलिखित हैं:

व्यावहारिक कमी

भारत में अनेक ऐसी परियोजनाएँ हैं, जिनका पर्यावरण पर व्यापक प्रभाव पड़ता है किंतु वे पर्यावरणीय प्रभाव आकलन की अनिवार्यता से बाहर हैं क्योंकि वे या तो सूची-1 में शामिल नहीं हैं अथवा उनमें किया गया निवेश अधिसूचना में बताई गई सीमा (₹ 50 करोड़) से कम है।

विशेषज्ञ समिति की संरचना एवं मानक *(Structure and Standards of Expert Committee)*

यह पाया गया है कि EIA अध्ययन करने के लिये बनाए गए समूह में विभिन्न क्षेत्रों, जैसे- पर्यावरणविद्, मानवविज्ञानी, समाजविज्ञानी आदि से संबंधित विशेषज्ञों की कमी है। प्रभाव आकलन में व्यापक पारिस्थितिकी एवं सामाजिक आर्थिक सूचकांकों की कमी होती है।

जन सुनवाई *(Public Hearing)*

परियोजना के प्रारंभिक दौर में सार्वजनिक टिप्पणी नहीं की जाती है, जिससे परियोजना के आखिरी दौर में विवादों का सामना करना पड़ता है। अनेक परियोजनाओं, जिनका पर्यावरण पर व्यापक प्रभाव पड़ता है, को अनिवार्य जन सुनवाई प्रक्रिया से बाहर रखा गया है।

गुणवत्ता *(Quality)*

पर्यावरण मंजूरी प्रक्रिया के संबंध में सबसे बड़ी चिंता EIA रिपोर्ट की गुणवत्ता है। सामान्यत: रिपोर्ट अपूर्ण होती है तथा संदेहास्पद आँकड़े प्रस्तुत करती है। रिपोर्ट में कई पक्षों को छोड़ दिया जाता है और अनेक महत्त्वपूर्ण सूचनाएँ भी इसमें अनुपस्थित रहती हैं। अनेक EIA रिपोर्ट किसी एक समयावधि के आँकड़ों पर आधारित होती हैं एवं ये आँकड़े पर्यावरणीय मंजूरी के लिये अपर्याप्त होते हैं।